



04 - जहरीली होती हवा
से गहराता सांसों का
संकट



05 - साहित्य की
नागरिकता पैशिक
धरातल पर होती है

A Daily News Magazine

इंदौर

बुधवार, 23 अप्रूव, 2024



इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

ग्र 10 अंक 27, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2 (डाक पंजीयन संख्या: MP/IDC/1529/2016-2018)



06 - खुली नालियों पर फर्फा
डलकर आना-जाना करते हैं
लोग, बना रहता है हास्टे...



07 - 'पुलिस को इलेव्टीनिक
इंटीलिजेंस के आधार पर
देनेंगे की ज़रूरत'

खबर

खबर

प्रसंगवश

शुभज्योति घोष

करीब ढाई महीने पहले बांग्लादेश की सत्ता गंवाने के बाद शेखु हसीना एक सैन्य विमान से दिल्ली पहुंची थी। उसके बाद उनको सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया है। सोलह मीडिया पर भी उनकी काहे तस्वीर समाने नहीं आई है। फोन पर उनकी बातचीत के कुछ अंडियों सामने आने के बावजूद इसका काम संतुष्ट हो गया है कि उन्होंना की ही आवाज है।

भारत सरकार के किसी प्रवक्ता या मंत्री ने अब तक इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है कि दिल्ली पहुंचने के बाद शेखु हसीना या उनके साथ आई छोटी बहन शेखु रिहाना कहा और कैसे है। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटर्व्यू तक में भी किसी ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। अब बीते 17 अक्टूबर की शाम को भारत सरकार ने औपचारिक रूप से केवल इतना ही कहा है कि वो भारत आई है। अब इस अतिथि के दर्जे के आधार पर ही उनको लंबे समय तक यह खाला जा सकता है। इसमें भारत सरकार को कोई दिक्षिण नहीं है। देश के पुनर्नामित और अतिथि के तौर पर उनको तासमान और सुविधाएं प्रियोंगी।

फिलहाल शेखु हसीना को राजनीतिक शरण देने की भारत की कोई योजना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि शेखु हसीना ने खुद भी राजनीतिक शरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। लेकिन भारत सरकार जानती है कि आगे चल कर आगे प्रस्ताव आता है तो इस मुद्रे पर तथाप राजनीतिक दल सहमति होंगे और शेखु हसीना को राजनीतिक शरण देने के मुद्रे पर राजनीतिक तौर पर आम सहमति बनाने में कोई दिक्षिण नहीं होगी।

यह बात सही है कि शेखु हसीना को भारत प्रवास के मुद्रे पर केंद्र सरकार ने पूरी तरह गोपनीयता बनाए रखी है। लेकिन सरकार के सामने ये साफ नहीं है कि उनको तकनीन दिये तक भारत में रखा होगा। दिल्ली के साउथ लॉक के एक शीर्ष अधिकारी अपनी निजी राय जाहिर करते हुए कहते हैं, 'इस गोंग दू बी ए लांग हॉल।' उनकी राय में सरकार इस हकीकत के लिए धीरे-धीरे तैयार हो रही है कि शेखु हसीना को लंबे समय तक भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी।

तो क्या अतीत में जिस तरह तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और अक्गुनिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह को सपरिवार राजनीतिक शरण दी गई थी, शेखु हसीना के मामले में भी कुछ वैसा ही सोचा जा रहा है? इस बारे जानकारों का जवाब इस प्रकार है-

'भारत की नज़र में फिलहाल शेखु हसीना एक 'पेस्ट', बट अंडर कम्प्लेशन' है। यानी वो देश की एक समानित अतिथि हैं जिनको विशेष परिस्थिति में मजबूरन भारत आना पड़ा है। भारत सरकार यह बात अच्छी तरह जानती है कि अपने देश में सुरक्षा के खतरे को देखते हुए वो भारत आई है। अब इस अतिथि के दर्जे के आधार पर ही उनको लंबे समय तक यह खाला जा सकता है। इसमें भारत सरकार को कोई दिक्षिण नहीं है। देश के पुनर्नामित और अतिथि के तौर पर उनको तासमान और सुविधाएं प्रियोंगी।

फिलहाल शेखु हसीना को राजनीतिक शरण देने की भारत की कोई योजना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि शेखु हसीना ने खुद भी राजनीतिक शरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। लेकिन भारत सरकार जानती है कि आगे चल कर आगे प्रस्ताव आता है तो इस मुद्रे पर तथाप राजनीतिक दल सहमति होंगे और शेखु हसीना को राजनीतिक शरण देने के मुद्रे पर राजनीतिक तौर पर आम सहमति बनाने में कोई दिक्षिण नहीं होगी।

फिलहाल ऐसा लगता है कि भारत शेखु हसीना को अतिथि के तौर पर रखना चाहता है, लेकिन शरण नहीं देना चाहता। 17 अक्टूबर को दिल्ली में विदेश मंत्रालय की नियमित सामाजिक बींकिंग में प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा, 'आप सबको बांग्लादेश की पूर्व

प्रधानमंत्री के भारत में रहने के बारे में जानकारी है। उन्हें सुझा कारोंगे से बहुत कम समय के नोटिस पर यहाँ आना पड़ा था।'

शेखु हसीना को जिन हालात में भारत आना पड़ा है, वैसी स्थिति में आने वाले किसी भी अतिथि को 'डिलिकिंग सेशन' से जुर्जरा पड़ता है और हसीना भी इसका अवाद नहीं है। यीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने उनको इस बारे में छीफ कर दिया है कि उनका दिक्षिण को उम्मीदें हैं। यानी उनको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। साथ ही उनसे बातचीत के आधार पर कुछ नोटस लिए गए हैं।

भारत के पूर्व राजदूत अजय विसारिया भी मानते हैं कि शेखु हसीना को जिन हालात में भारत आना पड़ा है, किंतु वैसा लंबे समय तक यह खाला जा सकता है। इसमें भारत सरकार को कोई दिक्षिण नहीं है। लेकिन शरण देने की साथ इस देश में रहने के अलावा भारत के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देश के कट्टनवियत तबके या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों में भी इस बात पर आम राय है कि संकट की इस बड़ी में भारत को शेखु हसीना के साथ खड़ा रहना ही होगा। ऐसा नहीं करने से भविष्य में दक्षिण प्रियोंगी या देखनी की प्रियोंगी देश का कोई नेता भारत की मित्रता पर भरोसा नहीं कर सकेगा।

दिल्ली के थिंक टैक आईटीएस्पी की सीनियर फेलो स्पृति पट्टनायक याद दिलाती है कि साल 1975 में शेखु मुजीब हव्याकांड के बाद शेखु हसीना ने जब सपरिवार भारत में रहने के लिए चाहता था, तब वो उनको तकनीकी रूप से राजनीतिक शरण नहीं दी गई थी। उस बात की उनको प्रवक्ता के तौर पर ही रखती है कि शेखु हसीना को जाहाज आप सबको बांग्लादेश की पूर्व

सुधारना के करीब आधी सदी बाद अब मौजूदा नंदें मोदी सरकार भी ठीक इसी रास्ते पर चलने का संकेत दे रही है। लेकिन मेहमाननवाजी का चरित्र बदलने के बावजूद वह आज भी मेहमाननवाजी ही है। भारत की यह में शेखु हसीना को अतिथि के तौर पर यहाँ रहने देना ही इस कृतीनीतिक समाज का सबसे समाधान है। हालांकि कई प्रवेशक नामताएँ हैं कि दिल्ली में शेखु हसीना की मौजूदी भारत और बांग्लादेश की नई सरकार के आपसे संबंधों में सेड़ा बन सकती है।

किसी हाई-प्रोफाइल विदेशी नेता को राजनीतिक शरण देने की स्थिति में सर्सप की घोषणा करनी पड़ती है। फैसला लेने से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ यहाँ पर विचार-विमर्श की जाता है। हालांकि ऐसा करना बाध्यतामूलक नहीं है। शेखु हसीना को राजनीतिक शरण देने के मामले में एक बड़ी सहृदयता यह है कि भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी संभवतः इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करेगी। शेखु हसीना को राजनीतिक शरण देने की स्थिति में एक और सहृदयता योगी कि सिर्फ इसी आधार पर उनके प्रत्येक दल के बालादेश की साँपें की मांग खरिज की जा सकती। लेकिन ऐसा करने से पहले बालादेश सरकार के साथ भारत के संबंधों में कड़वाहट पैदा होगी। फिलहाल बालादेश में भारत का निवेश और बहुत चलने वाली परियोजनाओं में उसकी हिस्सेदारी सैकड़ों में है, इसलिए यह भी देखना होगा कि दिल्ली यह खतरा मौत लेगी या नहीं।

(बीबीसी हिंदी पर प्रकाशित
लेख के संपादित अंश)

रूस-यूक्रेन जंग केवल बातचीत से रुकेगी, भारत मद्द को तैयार

रूस में द्विपक्षीय बातचीत से पहले बोले पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति से मिले गए



यूक्रेन युद्ध के बाद रूस में सबसे बड़ा आयोजन

सोनरेन की रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से रूसी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित ये अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस समिट में रूस के अलावा ईरान और चीन जैसे दूसरी देशों के अमेरिका की सीरीज़ चुनौती देते रहे हैं। पुरुष ने इसके जरिए परिचय को देश दिया है कि रूस अलग नहीं पड़ा। हालांकि युद्ध ने सम्मेलन से पहले इस बात से इनकार किया कि यह समझ परिचय विरोधी गठबंधन है।

भारत का हर प्रयास मानवता के समर्थन में है। हम जल्द शांति की बागली चाहते हैं। ये पीएम मोदी ने दिल्ली में दूसरी बार रूस घूमने वाले तकनीकी रूप से एक बार रह जाएगा। इसमें यूक्रेन और गोलियों से शांति संभव नहीं है। इसके बाद वे यूक्रेन दौरे पर भी गए थे। जहाँ उन्होंने जलतीको से कहा था—मैंने पुरुष ने कहा था कि ये जंग का समय नहीं है।

अररिया (एजेंसी)। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अररिया में एक विवादित बायांगम खड़ा कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाधिनायक बायांगम के दौरान ए

भोपाल कलेक्टर ने आधी रात लगाई अफसरों की वतास

सीएम हेल्पलाइन पर पैडिंग शिकायतों को लेकर की वन-टू-वन बात; एक दिन में निपटी 600 शिकायतें

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 28 अक्टूबर को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करेगे। भोपाल में भी हजारों शिकायतें पैडिंग हैं। ऐसे में अक्सर की नींद उड़ी हुई है। इसके चलते कलेक्टर कौशलेंट विक्रम सिंह ने आधी रात अधिकारियों की वतास लगाई और उनसे वन-टू-वन चर्चा की। मंगलवार को भी मीटिंग होगी।

संभवतः यह पहला मौका है, जब भोपाल कलेक्टर सिंह ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में सम्बोध ज्यादा खराब पर्यामेंस देने वाले डेढ़ दर्जन से ज्यादा विभागों के अधिकारियों की देर रात मीटिंग की। सोमवार-मंगलवार की रात 12.30 से रात 12.45 तक अन्नलाइन बैठक में जिला पंचायत सीईओ ऋतुपाज सिंह भी शामिल हुए।

हर देंग हो रही बैठक

इससे पहले सोमवार शाम को टीएल बैठक में कलेक्टर ने इन अधिकारियों को फटकार लानाकर देर रात तक दफ्तर में बैठकर काम करने के लिए कहा था। यह भी कहा था कि वे आधी रात को



100 दिन पुरानी शिकायतों पर ज्यादा जोर

भोपाल में 100 दिन पुरानी शिकायतों को निपटाने पर ज्यादा जोर है। कलेक्टर सिंह ने भी स्पष्ट कहा है कि ऐसी शिकायतों को अनावश्यक रूप से पैडिंग न रखें। 50 दिन पुरानी शिकायतें भी निपटाई जा रही हैं।

अन्नलाइन जुड़ कर शिकायतों के निराकरण का रिजल्ट पूछें। इसके बाद ये अधिकारी देर रात तक अपने दफ्तरों में बैठकर शिकायतों को बंद करने में जुटे रहे। बैठक में यह बात सामने आई कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण

में भोपाल 26वीं रैंकिंग पर है। राजस्व, मत्स्य, पशुपालन, सहकारिता, सामाजिक न्याय सहित अन्य डेढ़ दर्जन विभाग डी रैंकिंग में शामिल हैं। वह समाह महावैप्र मालती रथ समीक्षा जरूर करती है, लेकिन नई शिकायतों से अंकड़ा बढ़ा हुआ रहता है। राजस्व विभाग की नामांकन, सीमांकन, बटांकन समेत जीमीन से जुड़े मामलों को लेकर विभागीय हैं।

इसलाइन भी अंकड़ा बढ़ाता है। भोपाल में हर मंगलवार मालती रथ जानुवारी वाले जानसुनवाई होती है। जिसमें औसत 100 आवेदन आते हैं। इन शिकायतों को भी सीएम हेल्पलाइन में दर्ज किया जाता है। इसलिए अंकड़ा बढ़ा हुआ है।

कलेक्टर कौशलेंट विक्रम सिंह और जियं सीईओ ऋतुराज सिंह ने सोमवार को भी सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा की थी।

3 दिन में आधी शिकायतों के नियरकरण का टारगेट

अगले 3 दिन में आधी शिकायतों के नियरकरण का टारगेट रखा गया है। ताकि, सीएम के सामने पैडिंग शिकायतों के प्रेजेटेशन में भोपाल की स्थिति बेहतर रहे।

ये शिकायतें सबसे ज्यादा: नार नियम की ज्यादातर शिकायतें स्टील डॉग, अंतिक्रमी, सींजें, आवारा पशु, स्ट्रीट लाट्ट, बिल्डिंग परिसर, सफाई से जुड़ी हैं। हर समाह महावैप्र मालती रथ समीक्षा जरूर करती है, लेकिन नई शिकायतों से अंकड़ा बढ़ा हुआ रहता है। राजस्व विभाग की नामांकन, सीमांकन, बटांकन समेत जीमीन से जुड़े मामलों को लेकर विभागीय हैं।

इसलाइन भी अंकड़ा बढ़ाता है। भोपाल में हर मंगलवार मालती रथ जानुवारी वाले जानसुनवाई होती है। जिसमें औसत 100 आवेदन आते हैं। इन शिकायतों को भी सीएम हेल्पलाइन में दर्ज किया जाता है। इसलिए अंकड़ा बढ़ा हुआ है।

उन्होंने कहा कि न्याय सहित हमें क्राइम से बचने की ज़िक्र देती है। इसके लिए पुलिस में हूज रिक्लूटिंग करना चाही दूनिया में है और इस बानाए रखने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस फार्मस के लिए जिसमें भी बहुत ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। जब थानों में मौखिक या इलेक्ट्रॉनिकली एफआईआर दर्ज की जाए तो इसकी वीडियोग्राफी भी आज की आवश्यकता है।

'पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के आधार पर ट्रेनिंग की ज़रूरत'

भोपाल में पूर्व जरिट्स बोले- तकनीक से अपराध का ट्रेंड बदला है



सेमिनार का एंजेंडा पुलिस की वाकिंग-ट्रेनिंग में सुधार और पुलिस की नैतिका-कौशल विकास है।

अपराधियों ने अपराध की नई तकनीक अपनाई

जस्टिस बोस ने कहा कि, बदलते दौर में अपराधियों ने अपराध की नई तकनीक इस्तेमाल कर दिया है। इससे पुलिस के काम में कॉम्प्लेक्स की स्थिति बनने लगी है। पुलिस का हूज रिस्पोस देश और दुनिया में है और इस बानाए रखने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस फार्मस के लिए जिसमें भी बहुत ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। थाने में आने वाला है अपराधियों ने एप्पल एंड्राइव या एप्पल एंड्राइव का फेस होते हैं। थाने में आने वाला है अपराधियों ने एप्पल एंड्राइव का फेस होते हैं। थाने में आने वाला है अपराधियों ने एप्पल एंड्राइव का फेस होते हैं। थाने में आने वाला है अपराधियों ने एप्पल एंड्राइव का फेस होते हैं।

जस्टिस बोस बोले- देश में लाख क्रेस पैडिंग हैं

एनसीआरसी 2022 के अंकड़ों का जिक्र करते हुए जस्टिस बोस ने कहा कि, देश के 18 हजार से अधिक थानों में एक लाख से अधिक क्षेत्र के स्वरूप इंटरियोर स्टर पर पैडुंग करने का जिक्र कर कहा कि मानी लाइंग, आर्म्स ट्रैड, नाकोटिक्स, क्रिटो करेंसी, डाक्नेट अब लोकल लेवल के नहीं, इंटरनेशनल लेवल के क्राइम ही गए हैं और इसकी विवेचना में सूक्ष्मता ज़रूरी होती है। देश में अपराधियों ने एप्पल एंड्राइव का फेस होते हैं। थाने में आने वाला है अपराधियों ने एप्पल एंड्राइव का फेस होते हैं।

सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 20 प्रतिशत सस्ती बिजली

म.प्र.में स्मार्ट मीटर लगाकर काउंट करेंगे यूनिट; रात के टैरिफ में बदलाव नहीं

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में अप्रैल 2025 से सभी घरेलू उपकारियों को सुधार 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच 20 प्रतिशत कम दाम पर विजली मिलेगी। रात में इस्तेमाल विजली की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए उर्जा विभाग नवबर में विद्युत नियायक आयोग में ट्रैफिक पिटिशन दायर कर रखा है। सुनाई के बाद नए रेट का आदेश जारी किया जाएगा।

ऐसा इस्तेमाल सुमिक्षन हो रहा है, क्योंकि मध्यप्रदेश में रोजाना 2,380 मेगावाट सोलर इन्विट्रियरी बन रही है। अप्रैल 2024 से ही 10 किलोवाट या इससे ज्यादा की विजली खपत करने के दिन में 20 फीसदी कम दर पर विजली मिल रही है।

सरकारी शिशु मंदिर के भैया बहनों ने व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति हेतु नगर पंचायत परिषद, ऐलेक्ट्रॉनिक अलग-अलग गणना की जा सकती है।

योजना के तहत विजली कपशियों स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रही है। इनसे दिन और रात में इस्तेमाल की जा रही विजली परियोजना से अलग-अलग गणना की जा सकती है।

एक मेगावाट से रोज 4000 यूनिट बिजली

बिजली कंपनी से जुड़े एक्सपर्ट के मुताबिक, एक मेगावाट में कीरीब 4000 यूनिट बिजली प्रतिदिन बनती है। मध्यप्रदेश में मौजूदा सभी सोलर परियोजनाओं की क्षमता कीरीब 2380 मेगावाट रोजाना है। ऐसे में कोरिं 95.20 लाख यूनिट बिजली रोज केवल सोलर परियोजनाओं से मध्यप्रदेश की मिल रही है।

रोजा सौर परियोजना से देश में पहली बार राज्य के बाहर दिल्ली में जीरी कर्मसियल प्रोजेक्ट में विजली सप्लाई की गई थी। इसके अलग-अलग शायाम-जामिच-नीमच सौर परियोजना से विजली करने के साथ-साथ भारतीय रेलवे को अलग-अलग गणना की जा सकती है।

रोजा सौर परियोजना से देश में पहली बार राज्य के बाहर दिल्ली में जीरी कर्मसियल प्रोजेक्ट में विजली सप्लाई की गई थी। इसके अलग-अलग शायाम-जामिच-नीमच सौर परियोजना से विजली करने के साथ-साथ भारतीय रेलवे को अलग-अलग गणना की जा सकती है।

कार्यालयीन व्यवस्था को समझाया। इसी क्राइम में रेलवे स्टेशन पर स्टेशन प्रबंधक ने विभिन्न व्यवस्थाओं को भैया बहनों को समझाया। जिसमें ट्रेनों कि स्पेनल व्यवस्था, एवं स्टेशन प्रबंधक जी.एस. पैटेल एवं रामस्वरूप कुशाग्राहा ने सरकारी व्यवस्था को भैया बहनों एवं उनके साथ पूर्वों प्राचार्य, आचार्य को सहयोग किया गया।

किन गर यालिका अधिकारी राकेश मिश्रा, नगर पंचायत प्रबंध अध्यक्ष लाता यशवंश पटेल, अमित परसाई प्रबुद्ध दुबे, अधिकारी कमीटीरायी एवं स्टेशन प्रबंधक जी.एस. पैटेल एवं रामस्वरूप कुशाग्राहा ने सरकारी व्यशु मंदिर के भैया बहनों एवं उनके साथ पूर्व

इट विलक

‘जनसंख्या जिहाद’ का पलटवार या सियासी सत्ता संतुलन की प्री-प्लानिंग?



अजय बोकिल

दे | श के दक्षिणी राज्यों से आबादी बढ़ाने की जो आबादी उठी है, क्या वो ‘जनसंख्या जिहाद’ का पलटवार है या भविष्य में जगनीतिक सत्ता सूत्र अपने हाथों में रखने की प्री-प्लानिंग है अथवा देश में क्षेत्रवार आबादी के असंतुलन से होने वाले व्यापक राजनीतिक, सामाजिक और अधिक दुष्प्रभावों के मद्देजर ऐतिहासिक उपाय अभी करने का आग्रह है, इसे हमें गहराई से समझना होगा। दक्षिणी राज्यों के दो मुख्यमंत्रियों ने हाल में अपने प्रदेश के लोगों से आबादी बढ़ाने की जो अपील की है, या भारत में एक रिपोर्ट को रोकने के लिए अब तक चली आई रही ‘परिवार नियन्यों’ श्रीरा के ठीक विपरीत है। तो क्या इन नेताओं को बेतहासा बढ़ानी आबादी से जुड़े ख्यालों का भान नहीं है या फिर वो संसिद्धि परिवर्तों के अग्रह में छिपे आसन ख्यालों को भान कर रहे हैं? अंग्रेजों के मुख्यमंत्री चंद्रबबू नायडू ने हाल ही में कहा कि अब उनकी सरकार पुनरे कानून में बुनियादी बदलाव कर उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति देगी, जिनके 2 से ज्यादा लोकप्रिय देश में जहां आबादी का अर्थ जनशक्ति से ज्यादा ‘बोट’ से चुका है, वहां जनपालिंगीय संतुलन का अर्थ जगनीतिक सत्ता को काम सखना अथवा बदलने की ताकत से है। जब से देश में धार्मिक ध्वनिकण की राजनीति हावी हुई है, तब से यह जनसंख्या संतुलन के प्रति यह नजरिया और यह हुआ है। यह भावना तेजी से गहरा रही है कि किसी विशेष धर्म, जाति अथवा समुदाय की संख्या से ही सियासी शक्ति से अंजित किया जा सकता है और उस पर पकड़ लिया रखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बिधायक बदल अतीने खुले तौर पर घोषणा कर दी कि राज्य में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। हम यूपी पर राज करेंगे। इसमें सच्चाई जिन्होंने है, यह अलग बात है। लेकिन भावनावाक्त सर पर यह अपराध का अंतर्गत नहीं है, जहां बुजुर्गों की संख्या अधिक है। दक्षिण भारत में यह समस्या और गमीनी है क्योंकि युवा रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते हैं। परिणामस्वरूप कई गांवों में तो अब बुजुर्ग ही रह गए हैं। नायडू ने यह भी कहा कि दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर 1.6 तक गिर चुकी है, जो जायिये औसत 2.1 से काफी कम है। अगर हाव और घटती ही, तो 2047 तक बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी, जो कि वांछनीय नहीं है। चंद्रबबू के बयान के दूसरे ही दिन तमिननाडु के मुख्यमंत्री एम.के.सालिन ने भी लगभग उसी बात को दोहराया। हालांकि उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। हिंदू धार्मिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि संसदीय परिसीमन प्रक्रिया से दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने और छोटा परिवार का विचार छोड़ने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अतीत में, बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों की 16 बच्चों को नहीं बल्कि 16 तरह की संपत्ति करने और खुशहाल जीवन जीने का असीमित दर्ते थे। अब उन्हें सचमुच 16 बच्चे पैदा

करने चाहिए, न कि एक छोटा और खुशहाल परिवार रखना चाहिए।

वैसे नायडू के कथन में सच्चाई है कि बेशक आज भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश है। कर्ड पालेश प्रो-सेक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 65 फॉस्टरी 35 साल के नीचे की है। लेकिन तीस साल बाद यही आबादी 65 वर्ष की होगी। यानी भारत में हर पांचवा शख्स बुजुर्ग होगा। यह आबादी करीब 35 करोड़ होगी। यह वो आबादी होगी, जो सेवानिवृत अथवा कम कार्यकारी लोगों की है।

भारत जैसे लोकप्रिय देश में जहां आबादी का अर्थ जनशक्ति से ज्यादा ‘बोट’ से चुका है, वहां जनपालिंगीय संतुलन का अर्थ जगनीतिक सत्ता को काम सखना अथवा बदलने की ताकत से है। जब से देश में धार्मिक ध्वनिकण की राजनीति हावी हुई है, तब से यह जनसंख्या संतुलन के प्रति यह नजरिया और यह हुआ है। यह भावना तेजी से गहरा रही है कि किसी विशेष धर्म, जाति अथवा समुदाय की संख्या से ही सियासी शक्ति से अंजित किया जा सकता है और उस पर पकड़ लिया रखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बिधायक बदल अतीने खुले तौर पर घोषणा कर दी कि राज्य में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। हम यूपी पर राज करेंगे। इसमें सच्चाई जिन्होंने है, यह अलग बात है। लेकिन भावनावाक्त सर पर यह अपराध का अंतर्गत नहीं है, जहां बुजुर्गों की संख्या अधिक है। दक्षिण भारत में यह समस्या और गमीनी है क्योंकि युवा रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते हैं। परिणामस्वरूप कई गांवों में तो अब बुजुर्ग ही रह गए हैं। नायडू ने यह भी कहा कि दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर 1.6 तक गिर चुकी है, जो जायिये औसत 2.1 से काफी कम है। अगर हाव और घटती ही, तो 2047 तक बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी, जो कि वांछनीय नहीं है। चंद्रबबू के बयान के दूसरे ही दिन तमिननाडु के मुख्यमंत्री एम.के.सालिन ने भी लगभग उसी बात को दोहराया। हालांकि उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। हिंदू धार्मिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों की 16 बच्चों को कही जानी बाहर चले जाते हैं। यदि वांछनीय नहीं है। चंद्रबबू के बयान के दूसरे ही दिन तमिननाडु के मुख्यमंत्री एम.के.सालिन ने भी लगभग उसी बात को दोहराया। हालांकि उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। हिंदू धार्मिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों की 16 बच्चों को कही जानी बाहर चले जाते हैं। यदि वांछनीय नहीं है। चंद्रबबू के बयान के दूसरे ही दिन तमिननाडु के मुख्यमंत्री एम.के.सालिन ने भी लगभग उसी बात को दोहराया। हालांकि उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। हिंदू धार्मिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों की 16 बच्चों को कही जानी बाहर चले जाते हैं। यदि वांछनीय नहीं है। चंद्रबबू के बयान के दूसरे ही दिन तमिननाडु के मुख्यमंत्री एम.के.सालिन ने भी लगभग उसी बात को दोहराया। हालांकि उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। हिंदू धार्मिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों की 16 बच्चों को कही जानी बाहर चले जाते हैं। यदि वांछनीय नहीं है। चंद्रबबू के बयान के दूसरे ही दिन तमिननाडु के मुख्यमंत्री एम.के.सालिन ने भी लगभग उसी बात को दोहराया। हालांकि उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। हिंदू धार्मिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों की 16 बच्चों को कही जानी बाहर चले जाते हैं। यदि वांछनीय नहीं है। चंद्रबबू के बयान के दूसरे ही दिन तमिननाडु के मुख्यमंत्री एम.के.सालिन ने भी लगभग उसी बात को दोहराया। हालांकि उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। हिंदू धार्मिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों की 16 बच्चों को कही जानी बाहर चले जाते हैं। यदि वांछनीय नहीं है। चंद्रबबू के बयान के दूसरे ही दिन तमिननाडु के मुख्यमंत्री एम.के.सालिन ने भी लगभग उसी बात को दोहराया। हालांकि उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। हिंदू धार्मिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों की 16 बच्चों को कही जानी बाहर चले जाते हैं। यदि वांछनीय नहीं है। चंद्रबबू के बयान के दूसरे ही दिन तमिननाडु के मुख्यमंत्री एम.के.सालिन ने भी लगभग उसी बात को दोहराया। हालांकि उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। हिंदू धार्मिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों की 16 बच्चों को कही जानी बाहर चले जाते हैं। यदि वांछनीय नहीं है। चंद्रबबू के बयान के दूसरे ही दिन तमिननाडु के मुख्यमंत्री एम.के.सालिन ने भी लगभग उसी बात को दोहराया। हालांकि उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। हिंदू धार्मिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों की 16 बच्चों को कही जानी बाहर चले जाते हैं। यदि वांछनीय नहीं है। चंद्रबबू के बयान के दूसरे ही दिन तमिननाडु के मुख्यमंत्री एम.के.सालिन ने भी लगभग उसी बात को दोहराया। हालांकि उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। हिंदू धार्मिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों की 16 बच्चों को कही जानी बाहर चले जाते हैं। यदि वांछनीय नहीं है। चंद्रबबू के बयान के दूसरे ही दिन तमिननाडु के मुख्यमंत्री एम.के.सालिन ने भी लगभग उसी बात को दोहराया। हालांकि उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। हिंदू धार्मिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों की 16 बच्चों को कही जानी बाहर चले जाते हैं। यदि वांछनीय नहीं है। चंद्रबबू के बयान के दूसरे ही दिन तमिननाडु के मुख्यमंत्री एम.के.सालिन ने भी लगभग उसी बात को दोहराया। हालांकि उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। हिंदू धार्मिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में बुजुर्ग नवविवाहित ज